

shown encouraging performance in relation to the twin policy objective of extending help to developing countries and creating opportunities for export of capital goods, technology and know-how? If so, the details thereof.

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:**  
Discussions in between India and Soviet Russia about joint venture have taken place recently. Certain projects are under discussion which will be started in Iran, Nigeria and Algeria.

We are finalising proposals in regard to supply of some material and equipment for these projects which have been undertaken by the Soviet Union. In any joint collaboration the objective mentioned by the hon. Member, will be kept in mind.

**SHRI JANARDHANA POOJARY:**  
What is the policy of the Government so far as joint ventures are concerned? Is it for exploitation? If not, what guidelines have been given by the Government of India in order to prevent this exploitation?

**SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:**  
Joint ventures are undertaken with the consent of the beneficiary country, the country which would like to be benefited. So, there is no question of exploitation. There is the question of assisting the developing country.

**श्री श्री प्रकाश त्यागी :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि रूस के साथ मिल कर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कुछ उद्योगों की स्थापना का जो निर्णय किया गया है, उसके पश्चात् किन किन देशों ने अपने यहां उद्योग स्थापित करने की मांग की है। उन देशों के नाम क्या हैं और वहां पर पहले कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की जाएगी ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैंने तीन देशों के नाम बताये हैं: ईरान, अल्जीरिया और नाइजीरिया।

**श्री श्री प्रकाश त्यागी :** प्रश्न साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** साउथ ईस्ट एशिया के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

जब कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो मैं नाम कैसे बता सकता हूँ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि इट विल बी केप्ट इन माइंड। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी चीजों को वह अपने माइंड में रखेंगे और कितनी पर अमल करेंगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, क्या आपने सवाल सुना है ?

**अध्यक्ष महोदय :** क्वेश्चन नम्बर 448—श्री चतुर्भुज ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में बढ़ि

\* 448. **श्री चतुर्भुज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के तर्जुमारियों की संख्या में निरन्तर बढ़ि को देखते हुए सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की संख्या में बढ़ि करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष में कितने नये औषधालय खोले जायेंगे ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :** (क) जी हाँ।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 15 एलोपैथिक औषधालय, 4 आयुर्वेदिक, 4 होम्योपैथिक, एक यूनानी औषधालय और 2 दन्तचिकित्सा यूनिट खोलने की पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

इसके अतिरिक्त 1978-79 में विभिन्न शहरों में 20 एलोपैथिक औषधालय, 3 आयुर्वेदिक यूनिटें, 4 होम्योपैथिक यूनिटें, एक यूनानी और एक दन्तचिकित्सा यूनिट तथा 5 पॉलिक्लिनिक खोलने का भी प्रावधान है।

**श्री चतुर्भुज :** मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रश्न का पूरा उत्तर आया है। लेकिन मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि चालू वर्ष में 20 एलोपैथिक औषधालय, 3 आयुर्वेदिक यूनिट, 4 होमियोपैथिक यूनिट, एक यूनानी और एक दन्तचिकित्सा यूनिट तथा 5 पॉलिक्लिनिक कहां कहां खोले जायेंगे।

**श्री विनायक प्रसाद यादव :** अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं गेट नम्बर 1 पर आ रहा था। वहां पंद्रह बीस नौजवान किसी

एम० पी० को अन्दर नहीं आने देते हैं और हंगामा मचाये हुए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वहाँ रास्ता साफ करवायें, नहीं तो कोई माननीय सदस्य अन्दर नहीं आ सकते हैं। (व्यवधान) आपसे आग्रह और निवेदन है कि आप पहले रास्ते को साफ़ करवायें ताकि कोई माननीय सदस्यों को आने से न रोके। आप खुद जाकर वहाँ देखें (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I shall take immediate steps to clear them.

श्री चतुर्भुज : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह ठीक है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस प्रांत के अन्दर कौन कौन सी यूनिट उन्हींने खोली है ?

श्री जगवन्धी प्रसाद यादव : श्रीमन्, लिस्ट थोड़ी बड़ी है फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पर जिनका प्रावधान हम कर चुके हैं उनको बता देता हूँ। हम ने 26 यूनिट्स का प्रावधान किया है। दिल्ली में 7 एलोपैथिक यूनिट, 2 आयुर्वेदिक, 2 होम्योपैथिक और एक यूनानी यूनिट, अहमदाबाद में 3 एलोपैथिक, 1 आयुर्वेदिक, 1 होम्योपैथिक और 1 यूनानी यूनिट, लखनऊ में 3 एलोपैथिक, 1 आयुर्वेदिक, 1 होम्योपैथिक और 1 दन्त चिकित्सक, मेरठ में 1 एलोपैथिक, जयपुर में 1 एलोपैथिक यूनिट खोलने का प्रावधान किया है। बाकी जिन के बारे में कहा है कि प्रावधान कर रहे हैं वह कुछ विल्ली में कुछ है गाजियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, हैबराबाद, कानपुर, बंगलौर, पूने, बाम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में है। समूची लिस्ट पढ़ने में विलम्ब होगा, माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको दे सकता हूँ।

श्री चतुर्भुज : राजस्थान के अन्दर जयपुर के अलावा अन्य स्थानों पर कहां कहां खोलने का प्रावधान आपने किया है ?

श्री जगवन्धी प्रसाद यादव : सी जी एच एस डिस्पेंसरी खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार में जो काम करने वाले हैं, उनके 7500 परिवार चाहिए। जब तक इतने परिवार नहीं होते, तब तक हम नहीं खोल सकते। उसके लिए दूसरा प्रावधान करते हैं कि मेडिकल एड देते हैं जहां कम होते हैं और एथोराइज्ड डाक्टर वहां बहाल करते हैं जिस से कि उनसे वह लिखा कर वह ले लें और उसका हम रिइम्बर्समेंट कर देते हैं। जिन शहरों में हम करने जा रहे हैं उनकी सूची हमने दे दी है, वह 13 हैं और दो में और कर रहे हैं अहमदाबाद और एक और जगह में। (व्यवधान...) राजस्थान में और कोई दूसरा खोलने का प्रावधान नहीं है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिक्य तो खोलने जा रहे हैं लेकिन क्या यह सही है कि जो वर्तमान प्रौद्योगिक्य हैं उनमें डाक्टरों का भारी अभाव है और उस के कारण समूचित चिकित्सा नहीं

मिल पाती है, वो उस अभाव को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री जगवन्धी प्रसाद यादव : श्रीमन्, डाक्टरों की कमी जरूर है और उसको पूरा करने के लिए उपाय किए गए हैं। जो कठिन क्षेत्र हैं वहां डाक्टर ट्रांसफर होने पर जाते नहीं हैं उस के लिए हम ने यू० पी० एस० सी० से अलग से सेलेक्शन करने के लिए कहा है और यू० पी० एस० ने 270 डाक्टरों की सूची दी है। हमने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी वह जवाइन कर लें। दिल्ली या और दूसरी जो अच्छी जगहें हैं वहां के लिए भी हमारे पास यू पी एस सी की सूची आ गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्दी से जल्दी जवाइन करें।

श्रीमती रसीदा हक चौधरी : सी जी एच एस में एक्सपेंसिव मेडिसिन्स के मिलने में कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। तो मंत्री महोदय इस के लिए कोई व्यवस्था करेंगे जिससे वहां एक्सपेंसिव मेडिसिन्स के मिलने में दिक्कत न हो ?

श्री जगवन्धी प्रसाद यादव : जो दिक्कत होती थी उसको देखते हुए दिल्ली में जो सुपर बाजार है उससे हमने आग्रह किया है कि वह साढ़े नौ बजे नित्य प्रति अपने आदमियों को भेज कर जो सूची तैयार हो वहां पर मेडिसिन सप्लाई करने के लिए उसको लेकर उसी दिन उसको सप्लाई कर दें। इस तरह जो कठिनाई थी उसको देखते हुए उसको दूर करने प्रयास किया है और और भी जो सम्भव हो सकता है वह हम अवश्य करेंगे।

SHRI VAYALAR RAVI: Mr. Speaker, Sir, I do not know whether the hon. Minister had any occasion to visit the CGHS dispensaries. The accommodation and other facilities are very poor and the rush is very heavy. Under this background, will the Government improve the conditions in the CGHS and provide more doctors because of the heavy rush in the dispensaries?

श्री जगवन्धी प्रसाद यादव : यह ठीक है कि जितने डाक्टर है या जितनी अस्पतालों में एकोमोडेशन है उससे ज्यादा है ही रश है और इस लिए हमने अधिक डाक्टरों की व्यवस्था की है। यह भी हम सोच रहे हैं कि कै० दिल्ली के अस्पतालों को इम्ब्यू कर के उसको हम कम करें। लेकिन जब तक हम दिल्ली के अस्पतालों के साथ पैरिफेरल अस्पताल नहीं बना लेते हैं तब तक वह रश घटता नहीं है। अगर हम एक तरफ सफरदर्जंग को लें जहां पर साल में लगभग 13 लाख लोगों का इलाज होता है। पैमेंट और पेमेंट के साथ आने वाले लोगों का हिसाब लगायें तो 40-50 हजार लोग रोज आते हैं। यह भार

बहुत है। इस भार को दूर करने के लिए एक कमेटी एम एम सिद्ध की अध्यक्षता में बना दी गई है जो कि इस बात को देखेगी कि किस तरह से इसका समाधान किया जाये।

**Supply of Iron and Steel by SAIL to Kerala Steel Traders**

+

\*450. SHRI K. A. RAJAN:  
DR. VASANT KUMAR  
PANDIT:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from Kerala Steel Traders Association on the denial of supplies of iron and steel by SAIL stockyard to traders and for redress of their grievances; and

(b) if so, the details and Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK):  
(a) Yes, Sir.

(b) The Association represented that Cochin stockyard of SAIL was not supplying steel to the traders; it was also suggested, in the memorandum that at least 50 per cent of the materials received by the stockyards should be allotted to the trade. The policy regarding supply of steel to trade has been examined recently. It has been decided to supply a certain percentage of materials available in the stockyards to the trade. This decision is under implementation by SAIL.

SHRI K. A. RAJAN: These dealers were deprived of iron and steel for the last seven or eight months. In 1974-77, when there was a huge accumulation of stocks in the SAIL, they were even compelled to avail of those stocks and they were also threatened. Now their real demand is that they may be allotted at least 50 per cent of the iron and steel. I would like to know from the hon. Minister as to

what real order has been given on this.

SHRI BIJU PATNAIK: At no time, did the dealers ever get 50 per cent of the total production. But when there is a shortage, it is the duty of the Government to give priority to the consumers, especially to small scale consumers and that is what the Government's decision was a few months back. With the advent of large scale imports, while the position is becoming slightly easier, I have recently decided to give a certain percentage, however, small it may be, to the dealers so that they can open up their trade. On the average, I have given them 10 to 15 per cent on certain sections and about 5 to 8 per cent in some other sections. As the position improves, I shall continue to improve this percentage to the dealers.

SHRI K. A. RAJAN: I thank the hon. Minister for having waived the earlier restrictions. But still certain items are restricted, commanding a premium of not less than Rs. 50 per tonne in the market. That is disadvantageous. I would like to know whether the Minister would consider to waive this particular criterion also.

SHRI BIJU PATNAIK: If the hon. Member is not satisfied, I may say that GP and GC sheets are also in that 50 per cent. That should cover the question of the hon. Member.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: I would like to know from the hon. Minister whether he had received a similar complaint from Iron and Steel Merchants of Bombay. The percentage now settled by the Government is not uniform. Certain items like slow moving items, low-premium items, they have given to the traders, while the fast moving items are not given. And the plea that SAIL is catering to the small consumers is not correct because the small scale Industries corporations give the materials to all those units which are not even functioning. The materials always go to the black market and not to the traders. Will